प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 15 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 8 – 15 अप्रैल 2019 मूल्य पांच रूपए

क्या भाजपा भी सोशल मीडिया में फेक न्यूज का शिकार हो रही है

शान्ता की पीड़ा आडवाणी के ब्लॉग और जोशी के कथित पत्र से उठे सवाल

शिमला/शैल। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नाम से लाल कृष्ण आडवाणी को लिखा एक पत्र चर्चा मे आया है। यह पत्र ए..एन.आई के माध्यम से वायरल हुआ कहा जा रहा है क्योंकि पत्र के ऊपर एएनआई लिखा गया है। पत्र पर 12 अप्रैल की तारीख दर्ज है। इस पत्र के वायरल होने के दो तीन दिन बाद सोशल मीडिया में ही एएनआई और डॉ. जोशी के नाम से कहा गया है कि यह पत्र फेक है। लेकिन इस पत्र को लेकर सोशल मीडिया के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई गयी हो ऐसा अभी तक सामने नही आया है न ही इस संबंध में डॉ. जोशी की ओर से प्रिन्ट मीडिया या न्यूज चैनलज़ पर कोई खण्डन आया है। जबकि यह पत्र यदि सच में ही सही है तो यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है।

इस पत्र की गंभीरता आज के राजनीतिक वातावरण में और भी बढ़ जाती है। क्योंकि भाजपा के ही पूर्व मन्त्री अरूण शोरी, यशवन्त सिन्हां एक अरसे से रफाल सौदे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी रिव्यू याचिका स्वीकार कर ली है। भाजपा के ही पूर्व मन्त्री शत्रुघ्न सिन्हा एक अरसे से विपक्ष की सभाओं में शिरकत करते रहे हैं और अब कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शान्ता कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं को आज भाजपा ने पुन: चुनाव में नही उतारा है। 2014 में जब भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिये घोषणा पत्र जारी किया था उसमें आडवाणी और जोशी की मुख्य भूमिका थी। इनके चित्र उस घोषणा पत्र पर दर्ज थे। लेकिन आज जब 2019 का घोषणापत्र जारी हुआ है उसमें आडवाणी और जोशी कहीं नही है। बल्कि घोषणा पत्र जारी करने के समारोह में शामिल नही थे। भाजपा की मुख्य धारा से जिस तरीके से इन लोगों को बाहर किया गया है उसका देश की जनता में कोई अच्छा संकेत और सन्देश नही गया है। आडवाणी ने इस सबको कैसे लिया है यह पार्टी के स्थापना दिवस पर आये उनके ब्लॉग से देश के सामने आ गया है। आज पार्टी के अन्दर और बाहर चल रही मोदी शाह भक्ति पर अपरोक्ष में आडवाणी ने जो कुछ कहा है वह अपने मे सबके लिये आईना है।

हिमाचल के लोग जानते है कि शान्ता कुमार इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिये उन्होंने अपने तरीके से प्रचार अभियान भी छेड़ दिया था। लेकिन जब पार्टी ने उनको टिकट से बाहर कर दिया तब उनकी पीड़ा प्रदेश के सामने आ ही गयी। बल्कि अब तब सोनिया गांधी ने मोदी को वाजपेयी काल के 2004 के शाईनिंग इण्डिया की याद दिलाई तब शान्ता ने जिस ढंग से सोनिया की राय का समर्थन किया है उसके बाद शान्ता जैसे बड़े नेता को और कोई संकेत/संदेश देना शेष नही रह जाता है। क्योंकि राफेल सौदे के बाद फ्रांस सरकार ने जिस तरह से

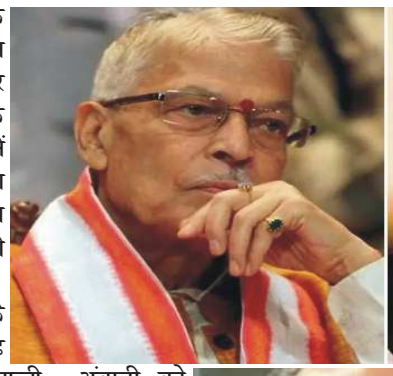

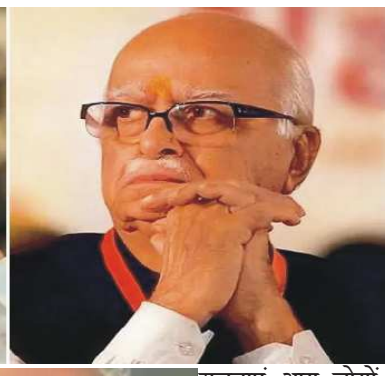

अंबानी को 1155 करोड़ की टैक्स राहत दी है उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही नही आज आरटीआई के तहत आरबीआई से मिली जानकारी में यह सामने आ गया है कि 2014 से 2018 तक मोदी सरकार के कार्यकाल मे 5,55,603 के ऋण राईट ऑफ कर दिये गये हैं। यह ऋण किन बड़े लोगों के रहे होंगे इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

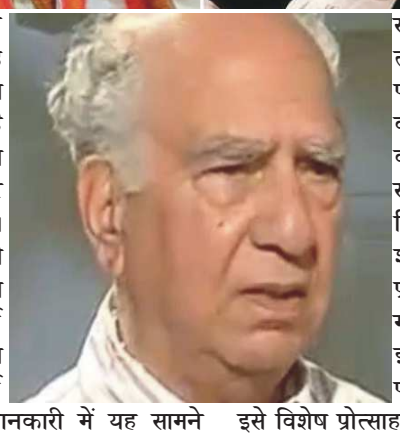

ऐसे में जिस पार्टी और सरकार के सामने ऐसे गंभीर सवाल जवाब मांगते खड़े होंगे उसकी अन्दर की हालत का अनुमान लगाया जा सकता है फिर इस तरह के परिदृश्य में जब पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो उनकी पीड़ा कहीं तो छलक कर बाहर आ ही जायेगी। फिर जब पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के मौके पर यह वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल नही थे तब इनको लेकर मीडिया में सवाल उठने स्वभाविक थे और यह उठे भी। संभवत: इन्ही सवालों के बाद अमितशाह, आडवाणी और जोशी से मिलने गये थे। इस पृष्ठभूमि में बहुत संभव है कि डॉ. जोशी की पीड़ा भी इस पत्र के रूप में छलक गयी हो। आज सोशल मीडिया पार्टीयों का बहुत बड़ा साधन बना हुआ है। बल्कि प्रिन्ट मीडिया की बजाये राजनीतिक दल सोशल मीडिया का ज्यादा सहारा ले रहे हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में काम दिया हुआ है। यह सोशल मीडिया के सक्रिय कार्यकर्ता किस तरह की सूचनाएं आम लोगों तक इस माध्यम से पहुंचा रहे हैं। क्या कोई नेता या कार्यकर्ता इन सूचनाओं की जिम्मेदारी ले रहा है शायद नही। फिर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तो डिजिटल इण्डिया के बहुत बड़े पक्षधर हैं उन्होने तो इसे विशेष प्रोत्साहन दिया है। वह इसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि करार देते हैं। लेकिन क्या इस डिजिटल इण्डिया और सोशल मीडिया की कोई विश्वसनीयता बन पायी है। आज इसमें किसी का भी अकाऊंट हैक किया जा सकता है। बहुत संभव है कि डॉ. जोशी का यह पत्र उसी हैकिंग का परिणाम हो। लेकिन इसमें यह सवाल जो जवाब मांगेगा ही कि जो न्यूज चैनल भाजपा नेताओं से ज्यादा भाजपा का प्रचार – प्रसार कर रहे थे वहां पर इस पत्र के फेक होने के समाचार क्यों नही आये। डॉ. जोशी ने किसी अखबार या न्यूज चैनल से बात करके इसका खण्डन क्यों नही किया? भाजपा/जोशी की ओर से इसमें अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नही करवाई गयी है। इस परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है कि पाठक इस पत्र को पढ़कर स्वयं अपनी राय बनायें।

डॉ.जोशी का कथित पत्र

DR MURLI MANOHAR JOSHI
Member of Parliament (Lok Sabha)
CHAIRMAN
Estimates Committee

52-B, Parliament House
New Delhi - 110001

ANI

प्रिय आडवाणी जी,

सप्रेम नमस्कार,

लोकसभा का पहला चरण संपन्न हो जाने के बाद अब परिणामों की तस्वीर कुछ-कुछ साफ़ नजर आने लगी है, कल देवकी नंदन मिश्र जी घर पर आये थे -कहने लगे की हम ने समय पर जनता का साथ नहीं दिया, ढेरों उलाहना के बीच उनकी एक बात मुझे भी अच्छी लगी कि हम दोनों को तो कम-से-कम सच्चाई जनता को बता ही देना चाहिए।

पहले चरण की 91 सीटों पर मतदान के गिरते प्रतिशत से स्पष्ट है कि बीजेपी को बमुश्किल 8-10 सीटें ही मिल पाएंगी, दूसरे और तीसरे चरण में बेहतर प्रदर्शन होने का भी कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। पिछली चर्चा में आप बीजेपी को 120 और मैं बीजेपी को 150 सीट दे रहा था परन्तु पहले चरण के मतदान के बाद आप सही साबित होते नजर आ रहे हैं।

मुझसे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का खूब दबाव आया पर तमाम विपरीत परिस्तिथियों के बावजूद अपना घर नहीं छोड़ा गया, बात अलग है की घर के लोगों ने हमें अपमानित कर घर से बाहर निकाल दिया है।

पिछले हफ्ते कानपुर से लखनऊ होते हुए इलाहबाद तक कार से यात्रा की, पूरे रास्ते नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और योगी के बड़े-बड़े पोस्टर दिखे। मुझे स्मरण है, जब इंदिरा जी का दौर था तब आपने और अटल जी ने उन विषम परिस्तिथियों में भी जिन सिद्धांतों को लेकर उत्साह के साथ इस पार्टी को बनाया था, आज उन्ही बुनियाद के पत्थरों को दरकिनार कर दिया गया है।

पिछली बैठक में आपने मुझे चुप करा दिया, अगली बैठक में मैं आपको चुप करा दूंगा लेकिन क्या हम दोनों की ये चुप्पी हमारे देश की जनता के साथ धोखा नहीं..? शत्रुघन और यशवंत जी की बात आपको बेशक उस दिन कडवी लगी, आपने अनापेक्षित प्रतिक्रिया भी दी पर आज मैं कह सकता हूँ कि वो सही थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवहारिकता को अपनी अंतरात्मा की आवाज के सामने डिगने नहीं दिया। हम और आप नैतिकता की आड़ में जिन मर्यादाओं का लिहाज कर रहे हैं, वह देश और समाज के सन्दर्भ में देखा जाय तो अनैतिक है।

बिटिया तीन दिन से कह रही थी, एक बार तो लिखो सो लिख रहा हूँ, बात तो फोन पर भी हो सकती थी पर पत्र इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इतिहास मेरे विचारों और मेरी परिस्तिथियों का सही-सही आकलन कर सके। जिस संविधान और प्रजातंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए आपने, अटल जी और हम सब ने पूरी उम्र न्योछावर कर दी, और आज जब उसी संविधान और प्रजातान्त्रिक मूल्यों की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है तब हम मौन हैं। आने वाली पीढियां ये जरुर पूछेंगी की जब इतना सब कुछ घटित हो रहा था तब उस दौर के नेता क्यों मौन थे..? तब उँगलियाँ हम पर भी उठेंगी।

मैं चाहूँगा की आप भी इस विषय पर मंथन करें कि हमारा निजी स्वार्थ और दलहित हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को कमजोर ना करे।

मैं जानता हूँ कि ये सब मेरे मन की बात है, हो सकता है राजनीतिक दृष्टी से ये सही भी ना हो और हो सकता है कि परिस्तिथियां सार्वजानिक तौर पर मुझे अपने इस पत्र पर कायम भी ना रहने दें, पर सच यही है। मैं रहूँ या ना रहूँ, यही दस्तावेज मेरी गवाही होगी।

शेष 24 तारीख को गाजियाबाद में मिलने पर..!

नई दिल्ली
१२ अप्रैल २०१९

भवदीय

(मुरली मनोहर जोशी)

Res : 6, Raisina Road, New Delhi – 110001 Telephones : 23718444, 23711144 Fax : 23711772
15/96H, Civil Lines, Kanpur 208 001 (Uttar Pradesh)
Telephone : (0512) 2399555 E-mail : murli@sansad.nic.in

हर्षोल्लास से मनाया गया 72 वां हिमाचल दिवस

शिमला/शैल। राज्य में 72वां हिमाचल दिवस उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराया और आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।

पुलिस उप अधीक्षक शक्ति सिंह ने परेड का नेतृत्व किया और पुलिस, होमगार्ड, भारत स्काउट एण्ड गाइड तथा एनसीसी के कैडेट्स ने मार्च पास्ट प्रस्तुत किया।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह सुन्दर पहाड़ी प्रदेश आज ही के दिन 30 छोटी-बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया था। राज्य की समृद्ध संस्कृति, उच्च परम्पराएं और असीम प्राकृतिक सौंदर्य, देव भूमि की विशिष्ट पहचान है। राज्य की वास्तविक शक्ति यहां के ईमानदार, कर्मठ और विकासशील लोग हैं तथा यहां शांतिपूर्ण वातावरण व सामाजिक सौहार्द कायम है, जो इसे अन्यों से अलग पहचान देता है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि 15 अप्रैल, 1948 को अस्तित्व में आने के बाद इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश ने तेज़ी से विकास का सफर तय किया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, दुर्गम क्षेत्र और अन्य जटिलताएं भी यहां के मेहनतकश लोगों के हौंसले व साहस को कम नही कर पाई। यहां के ईमानदार और विकासशील लोगों ने प्रदेश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो अन्यों के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेशवासी भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की सम्पत्ति हैं अत: जागरूक युवा ही देश को सशक्त कर विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। युवाओं को सार्थक ढंग से राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि देश के अनेक युवा नशे की गिरफ्त में हैं, जो देश के भविष्य के लिए घातक संकेत है। उन्होंने कहा कि नशे के विरूद्ध सभी को मिलकर कार्य करना होगा ताकि युवाओं को नशे के कुप्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने समाज के हर वर्ग से आग्रह किया कि वे इस सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती से पहल करें और प्रदेश को सशक्त करने के लिए आज शपथ लें।

उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश के उन महान स्वतन्त्रा सेनानियों को भी नमन किया जिन्होंने देश को स्वाधीन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही देश के लिए असंख्य कुर्बानियां देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश के गौरव की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गुरुकुल कुरुक्षेत्र से आए करीब 50 विद्यार्थियों द्वारा मलखम्भ और योग की प्रस्तुति थी। इस मौके पर जिला मतदान कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई लघु नाटिका, जिसमें लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया, भी आकर्षण का केंद्र रही।

देश के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका अहम: राज्यपाल

शिमला/शैल। पंजाब नेशनल बैंक के 125 वें स्थापना दिवस पर सोलन जिले के कंडाघाट में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि देश के आर्थिक विकास में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि पी.एन.बी. देश का पहला स्वदेशी बैंक है, जिसका गौरवमयी इतिहास रहा है। राष्ट्र नायक लाला लाजपत राय ने अन्य देशभक्तों के सहयोग से इस बैंक की स्थापना की थी। उनकी सोच लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की थी। एक पवित्र सोच के साथ आगे बढ़ते हुए अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए बैंक ने अपने को स्थापित किया और यह प्रसन्नता की बात है कि आज यह देश के अग्रणी बैंकों में शामिल है।

उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, जिस को दिशा देने का काम बैंकों द्वारा किया

एक लाख से ज्यादा लाभार्थीयों की सेवा बाबा साहब को समर्पित:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। हमीरपुर सांसदअनुराग ठाकुर ने बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की 128 वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब को सामाजिक समरसता और लोगों के हक़ की बुलंद आवाज़ बताया है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने एक वर्ष के अंदर अस्पताल सेवा द्वारा एक लाख से ज़्यादा लाभार्थीयों की सेवा की उपलब्धि को बाबा साहब को समर्पित किया है। सांसद अनुराग ठाकुर नादौन विधानसभा के सरेड़ी सिद्ध नामक जगह पर मंडल भाजपा द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज जब हम बाबा साहब की 128 वीं जयंती मना रहे है तो इस अस्पताल सेवा ने अपनी शुरुआत के मात्र एक साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का रिकार्ड बना दिया है। इस सेवा पर विश्वास जताने पर सांसद ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा इस अस्पताल सेवा के अंतर्गत 17 मोबाइल मेडिकल गाड़ीयों के ज़रिए हमीरपुर लोकसभा की सभी विधानसभाओं में लोगों को उनके घर द्वार स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। हमीरपुर लोकसभा की 800 पंचायतों में से अब तक 710 पंचायतों में पहुँचकर इन गाड़ियों ने लोगों का मुफ्त उपचार किया है। अब तक 40 से ज़्यादा फ्री जाँच मुफ्त दवाई और इलाज के ज़रिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाया जा चुका है। अस्पताल सेवा ने अभी तक लोगों के जाँच और इलाज पर ख़र्च होने वाले कुल 7 करोड़ से ज़्यादा रुपए की बचत की है। चलते फिरते अस्पताल सेवा का लाभ उठाने वाले सभी लाभार्थियों में 65% संख्या महिलाओं की है और साथ ही अस्पताल सेवा के कर्मचारियों में महिलाओं का प्रतिशत 50% से अधिक है। लोगों का स्वास्थ सेवा देने निकली अस्पताल सेवा की कुल 17 गाड़ियों ने अभी तक 55526 किलोमीटर की दूरी तय की है जबकि हिमाचल प्रदेश में सड़कों की कुल लम्बाई 36287 किलोमीटर ही है। आँकड़ों से साफ़ पता चलता है कि अस्पताल सेवा कितने वृहद स्तर पर लोगों का जीवन सुगम बना रही है और इस सेवा को लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं।

पोलीथीन हटाओ-पर्यावरण बचाओ अभियान का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से साप्ताहिक पॉलीथीन उन्मूलन कार्यक्रम 'पोलीथीन हटाओ-पर्यावरण बचाओ अभियान-2019' का शुभारम्भ किया। राज्यपाल ने इस अभियान के अन्तर्गत पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में सफाई अभियान का शुभारम्भ करते हुए करीब 1200 प्रतिभागियों को शहर के 14 अलग-अलग स्थानों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पॉलीथीन सैंकड़ों वर्षो तक गलता नहीं है और इससे जमीन की उर्वरा शाक्ति क्षीण हो जाती है। इसके कारण वर्षा जल जमीन के नीचे जा नहीं पाता और वनस्पति को उगने नहीं देता है। खाने की वस्तुओं के संपर्क में आने से कैंसर जैसे अनेक रोगों का यह कारण बनता है। इस प्रकार, पॉलीथीन पर्यावरण के लिए सबसे घातक है, जिसके उन्मूलन के लिए जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा एक विकराल रूप धारण कर प्रदूषण का कारण बन रहा है, जिसके प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और कुछ जागरूकता की कमी के कारण प्लास्टिक व पॉलीथीन पैकेट को खुले में फैंकते हैं। यही पॉलीथीन पर्यावरण के लिए खतरा बन जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण हैं और ऐसे अवसरों पर हमें प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इसके प्रबंधन के लिए ठोस पग उठाने चाहिए और एकत्रित पॉलीथीन को सड़क निर्माण, सीमेंट उद्योग व ईट निर्माण जैसे कार्यो में उपयोग में लाना चाहिए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि समर्पण से वे इस कार्य से जुड़ें और पर्यावरण को सुरक्षित करने में योगदान दें ताकि हिमाचल स्वच्छ, सुन्दर, हरित एवं प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बन सके।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों को पॉलीथीन उन्मूलन के लिए शपथ भी दिलाई। इससे पूर्व, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डी.सी. राणा ने राज्यपाल का स्वागत किया और सप्ताह भी चलने वाले इस अभियान की जानकारी दी।

स्वच्छता प्रतिभागियों में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवी, हिमाचल प्रदेश होम गार्ड के जवान, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम शिमला, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण परिषद् तथा अन्य विभागों से आए कर्मचारी शामिल थे।

जब स्टेपनी भी पंचर हो तो कैसे चलेगी रामलाल की गाड़ी:भाजपा

हमीरपुर/शैल। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री एवं प्रदेश सचिव विजय पाल सवारों ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमीरपुर का दूसरा टायर पंक्चर करेंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि भले ही विधानसभा चुनावों में हमीरपुर जिला की जनता ने कांग्रेस नेताओं की झूठी घोषणा और वायदों में आकर कुछ गलतियां कर दी थी किन्तु अब हमीरपुर की जनता लोकसभा के चुनावों में वैसी गलतियां नहीं दोहराएगी।

भाजपा नेताओं ने कहा कि हमीरपुर जिला वर्षों से भाजपा का अभेद्य गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि हमीरपुर की जनता जानती है कि जब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है तब-तब हमीरपुर से भेदभाव होता रहा है, हमीरपुर का विकास रुकता रहा है और रातों रात हमीरपुर के कई सरकारी कार्यालय दूसरी जगह शिफ्ट किये जाते रहे। इसके विपरीत हमीरपुर जिला को विकास के नाम पे अगर प्रदेश भर में किसी ने अग्रणी बनाया है तो वह भाजपा की सरकारों ने ही बनाया है।

रामलाल ठाकुर के ब्यान कि हमीरपुर का दूसरा टायर पंक्चर करेंगे पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि 5 बार चुनाव हारने वाले रामलाल ठाकुर के की गाड़ी के चारों टायर में पंचर हैं और स्टेपनी भी पंचर है, तो उनकी गाड़ी कैसे चलेगी । रामलाल ठाकुर को सातवीं बार हार का रिकार्ड बनाने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामलाल ठाकुर वैसे ही अभद्र भाषा का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं किन्तु फिर भी वह उन्हें कहना चाहते हैं कि इन चुनावों में अपनी भाषा पर संयम बरतें अन्यथा उनको उन्ही की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रामलाल ठाकुर इधर उधर ना हांके और मुद्दों की बात करें।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

पारिवारिक विवादों का फैमिली कोर्ट में होगा निपटारा

शिमला/शैल। धर्मशाला में अतिरिक्त न्यायिक परिसर ब्लॉक ए में फैमिली कोर्ट ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया।

फैमिली कोर्ट का कार्यभार जिला न्यायाधीश(फैमिली कोर्ट) पीआर पहाड़िया ने संभाल लिया है। पारिवारिक विवादों की सुनवाई अब इसी अदालत में होगी। पारिवारिक विवादों का निपटारा, पति पत्नी के आपसी मामलों की सुनवाई एवं उनका निपटारा जिसमें खर्च का दावा, तलाक के मामले, बच्चों की जिम्मेवारी एवं उनके पालन-पोषण के लिए खर्च इत्यादि मामलों का निपटारा अब इसी फैमिली कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आज का हाटी समुदायः विकास या पिछड़ापन?

प्रदेश का हाटी समुदाय एक लम्बे अरस से उन्हें जनजातिय का दर्जा दिये जाने की मांग करता है। यह मांग इसीलिये जायज़ हो जाती है क्योंकि इसी समुदाय का जो भाग उत्तराखंड में पड़ता और जौनसार बाबर के नाम से जाना जाता है उसे 1965 – 66 से ही जनजातिय दर्जा हासिल है। इस दृष्टि से हिमाचल के हाटी समुदाय की यह मांग एकदम जायज़ है । इस क्षेत्र का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों एवम् सांसदो के सामने हर चुनाव में यह बड़ी मांग होती जा रही है लेकिन हर बार आश्वासनों से अधिक इन लोगों को आज तक कुछ नही मिल पाया है। बल्कि 2014 में यहां के सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने बड़े ज़ोर से यह दावा /वायदा किया था और तब केन्द्र में नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब यह लगा था कि अब तो यह मांग पूरी हो ही जायेगी क्योंकि नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भी यहां के लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। इस बार फिर यह एक बड़ी मांग बनकर राजनेताओं के सामने है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों का चुनाव में समर्थन मांगने के लिये नेता किस हद तक इनसे क्या वायदा करते हैं और किसके वायदे पर यह लोग विश्वास करते हैं। इसी परिप्रेक्ष में हम पाठकों के सामने यहीं के एक युवा का लेख सामने रखने जा रहे है जो इस समुदाय को समझने में मद्द करेगा।

नितिश कुमार/शिलाई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का गिरिपार (ट्रांस गिरी) क्षेत्र उत्तराखंड के जौनसार बाबर से सटा हुआ है। जिला सिरमौर जो बाहरी हिमालय के शिवालिक खंड़ में स्थित है और तीन क्षेत्रों में विभाजित है। गिरीपार, गिरीआर व क्यारदा दून जिले के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर हाटी समुदाय निवास करती है और यह जिले की 45 – 50 फीसदी से अधिक जनसँख्या है। 1200 वर्ग किमी में फैले गिरिपार क्षेत्र में लगभग 3 लाख जनसँख्या बताई जाती है। गिरीपार (ट्रांसगिरी) क्षेत्र अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहां के रीती-रीवाज, त्यौहार, सभ्यता व संस्कृति देश से बिलकुल अलग है। इस क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्यौहार अलग प्रकार के हैं। यहां की बुढी दीवाली, माघी त्यौहार (भातियोज) देश के अन्य राज्यों से मेल नही खाते है। इसी तरह हर त्यौहार पर पकने वाले पारंपरिक पकवान भी अपनी अलग पहचान रखते है। गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाटी समुदाय के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि 1950 – 60 के दशक में यहाँ पर न बिजली और न ही सड़क हुआ करती थी जिसकी बजह से यहाँ के लोगो को दूर स्थित हाट (बाजार) पैदल चल कर जाना पड़ता था ताकि यहाँ के निवासी अपने लिए एक साथ नमक ला सके व अपनी खेती से उगाये गये अनाज को हाट (बाजार) में बेच सकें। ऐसे में यहाँ के लोग फसलों से हुई पैदावार को उठा कर पैदल आसपास में हाट पहुँचाया करते थे अपने समान को वहां पर बेच कर वापिस आते समय अपने लिए नमक व अन्य आवश्यक चीजों को लाया करते थे हाट जाने के कारण यहाँ पर बसने वाले लोगों को हाटी कहा जाने लगा। वहीं गिरिपार क्षेत्र से सटे जौनसार बाबर में बसे लोगों को जौनसारा कहा जाता है हाटी समुदाय के लोगों की समानता जौनसार बाबर के लोगों से काफी मेल खाती है वर्ष 1965 – 66 में जौनसार बाबर को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ परन्तु जौनसार बाबर से सटे हिमाचल के सिरमौर जिले का गिरिपार क्षेत्र जनजातीय घोषित होने से बंचित रह गया। जिसको लेकर यहाँ का हाटी समुदाय विभिन्न मंचों के माध्यम से समय समय पर संघर्ष करता आ रहा है। यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्तिथियों के कारण भले ही लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती नजर आती है लेकिन अपनी संस्कृति व परम्परागत व्यंजनों का आज भी यह क्षेत्र धनी है यहाँ की परिस्तिथियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर समय-समय पर विभिन्न प्रकार के मेले, त्यौहार मनाये जाते हैं विभिन्न त्योहारों में अलग – अलग व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर मनाये जाने वाले बूढी दिवाली, बिशु, माघी त्यौहार (भातियोज), खोडा, शांत, हरियालटी व यहाँ की शादियाँ देखने को मिलते है।

आज तकनीकी युग के दौर में जहां आधुनिक विज्ञान ने विश्व को उन्नति एवं विकास के लिए नूतन दिशा प्रदान की हैं। वहीं क्षति भी कम नहीं पहुंचाई है। क्योंकि जिस व्यवहारिक प्राविधिक ज्ञान को मानव ने अश्रांत प्रयत्न और दक्ष प्रज्ञा से अर्जित किया है। वह आज धुंधला पडता जा रहा है।

समय के साथ-साथ यहाँ पर सरकार के प्रयास से सड़क, शिक्षाऔर स्वास्थ्य से अब अछुता नहीं है। लेकिन इस नए प्रोद्योगिकी और परिवर्तनों के बावजूद आज भी यहाँ पर अनेकों परम्पराए व रीती रिवाज ऐसे बचे हुए हैं जो बदलते दौर से मेल नहीं खाते हैं जिसमे गिरिपार क्षेत्र में सदियों से चली आ रही खर्चीली प्रथाएं व परम्पराएं है जो समय के साथ साथ और ज्यादा खर्चीली होती चली है इन प्रथाओं में हर साल मनाया जाने वाला भातियोज त्यौहार गिरीपार क्षेत्र में प्रसिद्ध है, इस मौके पर यहां हर घर में 25 से 30 हजार के बकरे तो काटे जाते हैं। गिरिपार क्षेत्र में औसतन 11 जनवरी को 45 से 50 करोड़ के बकरे काटे जाते थे। पुराने समय में जहाँ यहाँ का प्राकृतिक वातावरण भिन्न था वही उस समय में उनका व्यवसाय भी भेड़ बकरी पालना होता था जिस के कारण इसकी उपलब्धता भी आसानी से हो सकती थी। लेकिन आज के समय में परिस्थितियां बिलकुल ही अलग हैं न ही किसी के घर में बकरी पाली जाती है और न ही हर घर की आर्थिक स्थिति मजबूत है जिस से हर घर में उस दिन के लिए बकरे को खरीद कर लाना पड़ता है जो हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है।

देवता के प्रांगण में मनाई जाने वाली शांत भी एक खर्चीली परम्परा है जो हर 30 से 40 साल बाद मनाई जाती है जिसमे 20 से 25 गाँव के लोग शिरकत करते है देवता और देवी के लिए बकरों को बलि के रूप में काटा जाता है जिसमे काफी पैसों का खर्च हो जाता है। इतना सारा खर्चा उठाने के लिए गाँव के हर व्यक्ति को उसके खर्चे का हिस्सा देना पड़ता है जो हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है।

वहीं 3 से 4दिन तक चलने वाली खर्चीली शादी (बारी का हूदा) भी मशहूर है जो आज के समय में बेहद खर्चीला व धन की बर्बादी है दिन प्रति दिन खर्चीली होती इन शादियों में 15 से 20 बकरे काटना, शराब का अत्यधिक सेवन करना, 15 से 20 टिन घी, डीजे व अन्य महंगी – महंगी चीजों का इस्तेमाल करना जिस से हर एक शादी में औसतन 15 से 20 लाख का खर्चा आ जाता है। इन खर्चीली प्रथाओं व परम्परा को छोड हाटी समुदाय को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है वहीँ प्राचीन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी बोली, बुअरा, खुमली, नाटी और यहाँ के लोक संगीत इत्यादि को संजोये रखने की भी आवश्यकता है. जिस से हाटी समुदाय के विकास के साथ साथ प्राचीन संस्कृति भी बची रहे।

मंडी की जनता पंडित सुखराम को रौद्र रूप दिखाएगीःभाजपा

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा जिला मंडी के अध्यक्ष रणवीर सिंह और कुल्लू के भाजपा जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने मंडी से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 19 मई 2019 को पंडित सुखराम को यह पता लग जाएगा की उनका स्थान कहां है, इन नेताओं ने कहा कि मंडी की जनता पंडित सुखराम को अपना रौद्र रूप दिखाएगी। इन नेताओं ने कहा कि पंडित सुखराम का पूरा परिवार प्रारंभ से ही अवसरवाद की राजनीति करता रहा है और विकास में रुचि लेने के बजाय शुरू से अपने परिवार के विकास में जुटा है। इस परिवार के नेताओं की सोच अपने परिवार तक ही सीमित है और इस परिवार ने अब तक 5 बार दल बदलकर कर हिमाचल प्रदेश में एक नया इतिहास लिखा है, जिसके लिए प्रदेशवासी इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि सुखराम परिवार हमेशा अहंकार की भाषा बोलता है और यदि उन्हें इतना ही अहंकार है तो अनिल शर्मा विधायक पद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव में जाएं तो उन्हें अपनी स्थिति का पता चल जाएगा कि वह कहां खड़े हैं । इन नेताओं ने कहा कि इस परिवार को जहां महत्व नहीं मिलता वहां इनका दम घुटने लगता है। अब जब भाजपा में पोते को टिकट नही मिला तो पोत्र मोह में पार्टी छोड़कर फिर कांग्रेस में चले गए। इनके इस चरित्र और तमाशे को जनता लगातार देख रही है और अब इस परिवार की राजनीति का अंत होगा।

भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी को न तो पहले पंडित सुखराम की दया की जरूरत थी और न ही आज है। प. सुखराम जब भाजपा में नहीं थे उससे पहले भी प्रदेश में अपनी सरकार बनाती रही है। भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है जिसकी सदस्य संख्या पूरे विश्व में सर्वाधिक है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के नेतृत्व में विशवास बढ़ा है। एक बार फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनायेगी।

लोस चुनाव प्रचार के लिये कांग्रेस महिला सेवादल की टीम गठित

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस महिला सेवादल की पदाधिकारियों को जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किया गया है जो कि प्रभार वाले जिले में जिला कांग्रेस कमेटी तथा वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बनाकर कांग्रेस सेवादल की महिला पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेगी।

नियुक्त किये गये जिला प्रभारियों में प्रदेश उपाध्यक्ष सुषमा चौधरी को जिला चम्बा तथा ऊषा मेहता को जिला मण्डी का प्रभार सौंपा गया है।

प्रदेश सचिव लोकेश्वरी को जिला कुल्लू, नीलम ठाकुर को जिला सोलन, समीरा शर्मा को जिला सिरमौर, काजल शाहिन को संगठनात्मक जिला देहरा, राधा ठाकुर को संगठनात्मक जिला पालमपुर, सरिता चंदेल को जिला शिमला शहरी का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

प्रदेश सचिव सुन्दर बाला को जिला शिमला ग्रामीण, बर्फी देवी तथा द्रोपती दत्ता को जिला बिलासपुर, ज्ञान कुमारी कौंडल को जिला संगठनात्मक सुन्दरनगर, सुमना देवी को जिला ऊना, रेखा सोनी को जिला हमीरपुर, विशाल देवी को संगठनात्मक जिला नुरपुर, गटुक अंगमो को जनजातीय जिला लाहुल स्पिति तथा तारा मोयान को जनजातीय जिला किन्नौर का प्रभार सौंपा गया है। जिन पदाधिकारियों को जिलों का प्रभार दिया गया है वे शीघ्र ही आबन्टित जिला में जा कर जिला एवं ब्लाक महिला संगठको के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार में जुट जाने के निर्देश दिये गये है।

मतदान से ही मजबूत होता है लोकतंत्र

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत निर्वाचक प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाने, नए मतदाता बनाने व अधिक से अधिक मतदान के उद्देश्य से शिमला लोक सभा क्षेत्र के कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र (खंड) में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान के माध्यम द्वारा लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है।

इस कडी में राजकीय उच्च पाठशाला, धाली, राजकीय उच्च पाठशाला, पधेची, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, चियोग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, धरेच, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जुग्गर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, भराडिया, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चिखर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मुंडाघाट, में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) के नोडल अधिकारी दिलीप वर्मा और तारा चन्द ठाकुर ने अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को सम्बोधित किया। उन्होने प्रजातंत्र के मूल्यों को विकसित करने की जरुरतों पर प्रकाश डाला व कहा कि लोकतंत्र वास्तव में अधिकाधिक मतदान से ही मजबूत और समृद्ध होता है।

हिमाचल में जयराम सरकार बनने के बाद ही शुरू हुई विकास की लहरःशशि दत्त

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त ने कहा जब – जब केन्द्र में कांग्रेस सरकार आयी तब – तब हिमाचल के साथ सौतेला बर्ताव हुआ। जिससे यह पहाड़ी प्रदेश विकास की दौड़ मे पिछड़ता चला गया। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ही यहां विकास की लहर शुरू हुई है।

उन्होने कहा कि डबल इंजन को सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की गति से घबराये कांग्रेस नेता तब कहां थे जब पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश को दिया गया विशेष औद्योगिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा प्रदेश के दो मंत्रियों वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा के रहते केन्द्र की कांग्रेसनीत यू.पी.ए. सरकार ने प्रदेश से छीन लिया था?

शशि दत्त ने कहा कि 13वें वित्तायोग के दौरान पूरे देश को 150 प्रतिशत वृद्धि मिली तो हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश में भाजपा सरकार के प्रति दुराग्रहपूर्ण रवैया अपनाते हुए यह वृद्धि मात्र 50 प्रतिशत देकर प्रदेश के विकास को ग्रहण लगाने की कोशिश की थी। इसके विपरीत वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने प्रदेश के साथ हुए सारे भेदभाव को खत्म करके 14वें वित्तायोग में इस आर्थिक सहायता को 235 प्रतिशत कर दिया था।

भाजपा नेता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष लगाव के चलते नरेन्द्र मोदी ने न केवल प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की बहाली की बल्कि केन्द्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी को बढ़ा कर 42 प्रतिशत कर दिया। हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार से इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 10,500 करोड़ रू. की अतिरिक्त केन्द्रीय आर्थिक सहायता मिली है। यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधानमंत्री व केन्द्रीय मंत्रियों के साथ अच्छे समबन्धों से सम्भव हो पाया है।

ईश्वर मूर्तियों में नहीं है। आपकी भावनाएँ ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है।.....आचार्य चाणक्य

सम्पादकीय

धारा 370 का राग कब तक

भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनावों के लिये संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी हो गया है। यह संकल्प पत्र राष्ट्र सर्वप्रथम के दावे के साथ शुरू होता है। इसमें आतंकवाद पर सुरक्षा नीति के तहत यह कहा गया है कि नीति राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। इसमें सर्जिकल स्ट्राईक और एयर स्ट्राईक का हवाला देते हुए आतंकवाद और उग्रवाद के विरूद्ध जीरो टॉलरैन्स का दावा किया है। इसके लिये सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण करने घुसपैठियों की समस्या का हल करने के लिये सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करने के साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू करने के साथ ही पड़ोसी देशों से आये सभी हिन्दु, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाईयों को उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत में नागरिकता देने का वायदा किया गया है। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और धारा 35A को खत्म करने का संकल्प फिर दोहराया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर यही सब वायदे 2014 के घोषणा पत्र में भी किये गये थे।

भाजपा राष्ट्र को सर्वप्रथम मानती है और राष्ट्र सर्वप्रथम होना भी चाहिये। इसमें किसी तरह की मतभिन्नता नही हो सकती यह तय है। लेकिन राष्ट्र सर्वप्रथम के सर्वमान्य मानक क्या हैं इस पर एक खुली चर्चा की आवश्यकता है। क्योंकि जब वामपंथी को सीधे उग्रवाद की संज्ञा दे दी जायेगी तो यह चर्चा और भी जरूरी हो जाती है। वामपंथी उसी तरह एक विचारधाराएं हैं जिस तरह आर एस एस और समाजवाद विचारधाराएं हैं। यह विचार धाराएं समाज का आकलन कैसे करती हैं और उनके हिसाब से एक आर्दश समाज कैसा हो और उसका संचालन कैसे किया जाये उसके लिये नीति-नियम कैसे हों इसको लेकर इन सारी विचार धाराओं की मान्यताओं में मतभेद हो सकता है। लेकिन इस मतभेद के चलते किसी भी विचारधारा को उग्रवाद की संज्ञा देना सही नही होगा। इसी के साथ किसी भी विचारधारा को समाज पर बलपूर्वक लागू करना भी गलत है यह भी तय है। लेकिन आज संयोगवश यह स्थिति पैदा कर दी गयी है जिसमें मेरी ही विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है और उसे बलपूर्वक लागू करने में कोई बुराई नही है का चलन शुरू करने की बात की जा रही है। आज राष्ट्रवाद का एक ही मानक बन गया है कि यदि आप मेरी विचारधारा से सहमत नही है तो आप राष्ट्र द्रोही हैं। दुर्भाग्य से सत्तारूढ़ भाजपा और उसके नेतृत्व को लेकर यह धारणा बनती जा रही है कि जो इनसे सहमत नही है वह राष्ट्रवादी है ही नही। इसलिये जब एक ही वाक्य में वामपंथ को उग्रवाद की संज्ञा भाजपा अपने संकल्प पत्र में देगी तो निश्चित है कि समाज का एक बड़ा वर्ग इससे सहमत नही हो पायेगा।

इसी परिप्रेक्ष में जब जम्मू कश्मीर की समस्या पर भाजपा के संकल्प पत्र के माध्यम से देखने का प्रयास किया जायेगा तो सबसे पहले यह उभरता है कि इस समस्या को लेकर भाजपा का आकलन सही नही रहा है। भाजपा की केन्द्र में प्रचण्ड बहुमत के साथ सरकार रही है। यही नही जम्मू कश्मीर में भी भाजपा सत्ता में रही है। सारे अधिकार सरकार के पास थे लेकिन यह समस्या आज भी वैसे ही खड़ी है जैसे पहले थी। भाजपा ने 2014 में भी वायदा किया था कि कश्मीर से पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों को वहां वापिस बसायेंगें लेकिन पूरे कार्यकाल में एक भी परिवार का पुर्नवास नही हो सका है। आज 2019 में फिर यह सकंल्प दोहराया गया है। धारा 370 हटाने और यनिफाईड सिविल कोड लाने का वायदा 2014 में भी किया गया था और आज भी किया गया है लेकिन इन पांच वर्षो में इसके लिये कोई कदम तक नही उठाया गया। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में जम्मू-कश्मीर के विधान की धारा 35A (जिसके कारण धारा 370 को लाया गया था) को चुनौती देते हुए दायर हुई याचिका पर केन्द्र सरकार ने आज तक अपना पक्ष तक नही रखा है। सरकार के इस आचरण से यह स्वभाविक सवाल उठता है कि या तो भाजपा इस समस्या को एक खास मकसद के साथ जिन्दा रखना चाहती है ताकि उसको हर बार एक बनी बनाई समस्या उपलब्ध रहे जिसके माध्यम से हिन्दु-मुस्लिम का धुवीकरण करना आसान हो जाये। इस मुद्दे पर भाजपा और प्रधानमन्त्री से यह सवाल करना बनता है कि जब आप लोकसभा में इतने प्रचण्ड बहुमत के बाद भी कोई कदम नही उठा पाये है तो फिर आगे आपके सकंल्प पर किस आधार से विश्वास किया जाये। क्योंकि इस कार्यकाल में जितना बहुमत आपके पास था उसके साथ आप संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकते थे। जब जीएसटी के लिये संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता था तो इसके लिये क्यों नहीं?

जम्मू-कश्मीर की समस्या पर जब भी कोई सवाल उठता है तो सीधे कह दिया जाता है कि सीमा पार से घुसपैठ हो रही है। यहां पर सवाल उठता है कि आखिर यह घुसपैठ होने क्यों दी जा रही है। जितना सैनिक बल आज जम्मू-कश्मीर के भीतर तैनात है क्या उसको भी सीमा पर पोस्ट करके घुसपैठ को रोका नही जा सकता। जब जम्मू-कश्मीर के भीतरी भाग से सेना हटा ली जायेगी तब वहां पर आतंक करने वाले की पहचना करना आसान हो जायेगी। इस समस्या के हल के लिये जो भी नीति पहले रही है वह सफल नही हो पायी है यह स्पष्ट हो चुका है क्योंकि इसी कारण से वहां पर राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ नही करवाये जा सके हैं। आज तक सरकार और प्रधानमन्त्री विपक्ष को पाकिस्तान के साथ जोड़कर जिस तरह की टिप्पणीयां करते रहे हैं क्या उन सारी टिप्पणीयों का जवाब इमरान खान के वक्तव्य को माना जाये। क्योंकि प्रधानमन्त्री जब बिना न्यौते के नवाज़ शरीफ के यहां पंहुच गये थे और फिर वेद प्रकाश वैदिक हाफिज़ सईद से मिले थे। इन मुलाकातों में क्या चर्चा रही है उसको लेकर आज तक अधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नही आया है। इसलिये आज इमरान खान के ब्यान के बाद पाकिस्तान तथा जम्मू-कश्मीर की समस्या को लेकर सरकार के दृष्टिकोण पर अलग से सोचने की स्थिति खड़ी हो जाती है क्योंकि इस ब्यान पर सरकार और भाजपा की कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नही आयी है।

130 करोड़ देशवासियों के सपनों का नया भारत

मेरे प्यारे देशवासियों,

भाजपा एक बार फिर आपके पास आई है ताकि आपका आशीर्वाद लेकर भारत की इस विकास यात्रा को अबाधित, बिना थके, बिना रूके, एक नए उत्साह और उमंग के साथ जारी रख सके।

पांच साल पहले, 26 मई 2014 को ऐतिहासिक जनादेश मिलने के बाद भारत के सर्वांगीण विकास के इस संकल्प के साथ यह यात्रा शुरू की थी।

उस समय, भारत के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां थी-हमारी अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति मे थी तथा चारों ओर निराशा का वातावरण था। भ्रष्टाचार विकराल रूप ले चुका था। अपने नागरिकों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर पाने में, भारत की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया जाता था।

लेकिन, अगर चुनौतियां बड़ी थी, तो एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने का हमारा संकल्प भी मजबूत था। 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और उनके कौशल के बलबूते, अभूतपूर्व रूप से जन भागीदारी के साथ हमने अवरोधों को अवसरों में, अवनति को विकास की गति में और निराशा को आशा में बदला।

जो चीज़ें कभी नामुमकिन लगती थी, उसको हमने तेज़ गति के साथ धरातल पर उतारा। पिछले पांच वर्षो में प्रत्येक भारतीय परिवार को जन-धन योजना के कारण बैंक खाता मिला, 50 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान भारत की बदौलत बीमारी से लड़ने का हौसला मिला और असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक लोग अब पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान ने जन आंदोलन का रूप ले लिया और पांच सालों में स्वच्छता का दायरा 38% से बढ़ कर आज 99% के करीब पहुंच गया है। मुद्रा योजना के कारण अब छोटे शहरों के युवाओं के लिए उद्यमी बनना संभव हुआ है। 5 लाख रूपये तक की आय वाले नव-मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों को अब आयकर से छूट मिल गई है।

हमारी सरकार ने भविष्य की सोच के साथ, तेज़ी से इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर किया है। सड़कों और रेलवे लाईनों के निर्माण की गति दोगुनी हो गई है। भारत के पास अब और भी अधिक अच्छे और आधुनिक बंदरगाह हैं। 2014 तक अंधेरे में रहने वाले 18,000 गांव अब ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयासों से प्रकाशमान हो गए हैं। सौभाग्य योजना के माध्यम से 2.6 करोड़ से अधिक घरों को रोशन किया गया है। पिछले पांच वर्षो में बने 1.5 करोड़ घरों ने लाखों लोगों को बड़े सपने देखने की आज़ादी दी है। पिछले पांच साल का हमारा कार्यकाल साक्षी है कि कैसे देश की विकास यात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले सकती है।

हमारा राष्ट्र अब निर्दयी आतंकी ताकतों के सामने लाचार नहीं है। देश की शांति और एकता के माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली हर विनाशकारी विचारधारा को करारा जवाब दिया गया है। उन्हें पहली बार सूद समेत उन्हीं की भाषा मे कड़ा जवाब मिला है।

पूर्वोतर भारत जो अब तक अलग थलग रहता था, में आज अभूतपूर्व विकास हो रहा है। पूर्वोतर आज देश की मुख्यधारा से मज़बूती के साथ जुड़ गया है।

केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। सेना के गलियारों में बिचौलियों की मौजूदगी इतिहास बन चुकी है। अब फैसले कुछ चुनिन्दा लोगों के निजी स्वार्थ के बजाए सभी भारतीयों के सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर लिए जाते हैं। जन-धन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी ने 8 लाख से अधिक फर्जी लाभार्थियों की पहचान मे सहायता की है और 1 लाख करोड़ से अधिक रूपये की चोरी को रोका है। काले धन को सफ़ेद करने से रोकने के लिए व्यवस्थाओं को मज़बूत किया गया है। भ्रष्टाचारियों में आज डर है।

आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। विदेशी निवेश में रिकार्ड वृद्धि से यह स्पष्ट है कि दूनिया भारत की अपार क्षमताओं से परिचित हुई है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और हवाला की रोकथाम जैसे विषयों पर भारत के रूख ने इन्हें वैश्विक मुद्दा बना दिया है।

साथियों, ''संकल्पित भारत, सशक्त भारत'' इस पत्र में आपको पिछले पांच सालों में जिन चुनौतियों को देश ने परास्त किया है उनके बारे में, उनसे निपटने के लिए 130 करोड़ भारतीयों द्वारा किए गए अदम्य प्रयासों के बारे में और आने वाले कल के लिए हमारे सामूहिक संकल्प की झलक मिलेगी।

पिछले पांच वर्षो में हमने बहुत कुछ हासिल किया है और आगे हम विकास की गति और विस्तार को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पित है। ऐसे दो संकल्प हैं जो मेरे हृदय के बेहद क़रीब है- 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना और सबको घर। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन से यह अवश्य संभव होगा।

मैं भारत के लाखों जागरूक, प्रतिबद्ध और देशभक्त नागरिकों का धन्यवाद करता हूं, जिनके मूल्यवान सहयोग से यह ''संकल्पित भारत, सशक्त भारत'' पत्र तैयार हो पाया है और सही मायनों मे लोगों की आवाज़ बन पाया है।

एक मजबूत और निर्णायक सरकार के लिए 2014 में आपके वोट ने हमें पांच वर्षो की छोटी सी अवधि में पांच दशकों के वंशवादी शासन की बुराइयों को दूर करने में सक्षम बनाया। अब जब इन बुराइयों पर हम विजय पा चुके हैं, तो उस गति की कल्पना करें जिसके साथ हम आने वाले समय में काम कर सकते हैं।

अगले पांच साल अहम अहम हैं क्योंकि 2022 में हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनायेंगे। इस देश के महान सपूतों ने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया ताकि हम आजादी की खुली हवा में सांस ले सकें। उनके सपनों का भारत बनाना, आज हम में से प्रत्येक का दायित्व है।

2047 में, हमारा राष्ट्र स्वतन्त्रता के सौ साल पूरे करेगा। आइए हम सब मिल कर सोच-विचार करें कि 2047 तक हम कैसा भारत चाहते हैं। भाजपा अगले पांच वर्षो में 2047 के भारत की नींव रखने की प्रतिज्ञा करती है। आइए अब हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करने में जुट जाएं।

विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं की कार्य संस्कृति और काम को देखने के बाद, आज भारत के लोग आश्वस्त हैं कि अगर कोई पार्टी है जो देश की समस्याओं का समाधान कर सकती है, तो वह भाजपा है। 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र भारत के कोने कोने तक गूंजा है। भाजपा हर भारतीय की पार्टी है। यह ऐसी पार्टी है, जो जमीनी स्तर पर 24 घंटे काम करती है। इसीलिए, हमें जो जनता का स्नेह और समर्थन मिला है, वह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है।

नया भारत अतीत की बेड़ियों से आज़ाद हो चुका है। आज हमारा देश बड़े सपने देखने की हिम्मत भी करता है और उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखता है।

आइए हम सब मिलकर एक मजबूत और सर्वसमावेसी भारत के निर्माण की दिशा में काम करें जहां हर भारतीय का सम्मान, समृद्धि, सुरक्षा और आगे बढ़ने के अवसर सुनिश्चित हों।

वन्दे मातरम!

नरेन्द्र मोदी

किसानों और राष्ट्रवाद के सहारे भाजपा का संकल्प पत्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व ने पिछले पांच वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इसी नीति पर हम आगे बढ़ेंगे।

आतंकवाद पर सुरक्षा नीति

हमारी सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। इसके उदाहरण हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक है। हम आतंकवाद एवं उग्रवाद के विरूद्ध ''जीरो टॉलरेंस'' की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए 'फ्री हैंड' की नीति का अनुसरण करते रहेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा

अपने सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाएंगे-हम रक्षा से जुड़े बाकी उपकरणों एवं हथियारों की खरीद तेज करगें। सुरक्षा बलों की हमला करने की क्षमता सुदृढ़ बनाने हेतु सैन्य बलों को आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए हम सघन प्रयास जारी रखेंगे।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे-रक्षा उपकरणों की खरीद में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि सबसे आधुनिक एके-203 स्वचालित राइफल्स बनाने की फैक्ट्री की नींव 'रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत अमेठी में रखी गई है। हम 'रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया' को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि रक्षा उपकरणों का स्वदेश में ही निर्माण हो सके। इससे रोजगार सृजन होगा और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

सैनिकों का कल्याण

हमारी सरकार ने लंबे समय से लंबित 'वन रैंक, वन पैंशन' को लागू कर सेवानिवृत सैन्यकर्मियों के हितों के प्रति अपने संकल्प को प्रतिबद्धता से पूरा किया। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सेवानिवृत सैन्यकर्मियों के पुनर्वास के लिए अधिक प्रभावी ढांचा तैयार करने का वादा करते हैं। इस प्रयास के अंतर्गत सशस्त्र बल के सैनिकों के सेवानिवृत होने से तीन वर्ष पूर्व उनकी पसंद के अनुसार ही उनके पुनर्वास की योजना आरम्भ कर देंगे। इसमें कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, आवास एवं उद्यम आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल होगा।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

हम केन्द्रीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए उनकी कार्य क्षमता और दक्षता में वृद्धि करेंगे, जिससे वह आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना सुदृढ़ता से कर सकें।

हम राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी अपनी पुलिस आधुनिकीकरण की पुनरीक्षित योजना के अंतर्गत सहायता मुहैया कराएंगे। राज्यों में पुलिस सुधार का कार्य भी तेजी से किया जाएगा, जिससे कि वह साइबर-क्राइम जैसे नए प्रकार के अपराधों से लड़ने में सक्षम हो सकें और नागरिकों, विशेष तौर पर कमजोर एवं असहाय वर्गों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों।

घुसपैठियों की समस्या का समाधान

घुसपैठ से कुछ क्षेत्रों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान में भारी परिवर्तन हृआ है और स्थानीय लोगों की आजीविका तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता पर एन आर सी का कार्य किया जाएगा। देश में चरणबद्ध तरीके से चिन्हित करके इसे लागू करेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में Illegal Immigration रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे। इसके लिए हम देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तकनीक के प्रयोग (स्मार्ट फेंसिंग) का पायलट प्रोजेक्ट धुबरी (असम) में लागू किया गया था, उसको हम सभी सीमाओं पर लागू करेंगे।

सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करेंगे

हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक और आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे कि ये क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में और भी अधिक मजबूती से योगदान करने के साथ-साथ, अन्य क्षेत्रों के बराबर, देश की उत्तरोत्तर प्रगति से पूरी तरह और भी अधिक लाभ ले सकें।

अपने पड़ोसी देशों से व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन में सहूलियत लाने के लिए 6 इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है और एक निर्माणाधीन है। हम इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए 2024 तक 14 और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण करेंगे, ताकि हमारा पड़ोसी देशों के साथ व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन में और अधिक सहूलियत हो सके। इनके निर्माण के बाद अनुमान है कि हमारा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ व्यापार मुख्यत: इन्हीं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के द्वारा होगा।

तटवर्ती सुरक्षा

हम राज्यों में तटवर्ती पुलिस थानों की स्थापना, समुद्री एवं तटवर्ती सुरक्षा सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना, द्वीप सूचना प्रणाली एवं राष्ट्रीय तटवर्ती पुलिस अकादमी के लिए आधुनिक उपकरण प्रदान करने एवं धन आवंटित करने हेतु तटवर्ती सुरक्षा योजना लागू कर तटवर्ती सुरक्षा को प्रभावी रूप से सुदृढ़ बनाएंगे। इसके उपरांत हम भारत की लंबी तटसीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाना जारी रखेंगे।

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी)

हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी) को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पूर्वोत्तर राज्यों से उन वर्गों के लिए मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए सभी प्रयास करेंगे, जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है। हम पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

भारत के पड़ोसी देशों से आए सभी हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई को उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाएगी।

वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला

हमने वामपंथी उग्रवाद के विरूद्ध बहुत सख्त कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप इन उग्रवादियों का कार्य क्षेत्र सिमट कर रह गया है। अगले पांच वर्षों में हम इसके विरूद्ध और अधिक कारगर कदम उठाएंगे, जिससे कि अगले पांच वर्षों में इस खतरे को दूर करने में हम सफल हो सकें। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में हमने विकास के कार्यों, जिसमें सड़क, मोबाईल फोन, स्कूल, चिकित्सा सेवा शामिल है, पांच वर्षों में बहुत प्रगति की है। हम इस कार्य को और ज्यादा गति से चलाएंगे ताकि ये पिछड़े क्षेत्र भी इन सुविधाओं के लाभ से आगे आ सकें।

जम्मू – कश्मीर – धारा 370

पिछले पांच वर्षों में हमने निर्णायक कारवाई और एक दृढ़ नीति के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और राज्य के हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं।

हम धारा 35A को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि धारा 35A जम्मू कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ़ भेदभावपूर्ण है। यह धारा जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधा है। राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे और हम पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) और छंब से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

किसानों की आय दोगुनी

भाजपा सरकार के वर्तमान कार्यकाल के प्रारंभ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने को मिशन के रूप में लिया। हम इस लक्ष्य को 2022 तक पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

किसान कल्याण नीति

☞ सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना-हमने 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों के लिए आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' आरम्भ की है। हम इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसे देश के सभी किसानों के लिए लागू करेंगे।

☞ छोटे और सीमांत किसानों के लिए पैंशन-हम देश में सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन की योजना आरम्भ करेंगे, जिससे कि 60 वर्ष की आयु के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

☞ **कृषि – ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रूपये का निवेश**-हम कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रूपए का निवेश करने को प्रतिबद्ध है।

☞ **ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण** - हम 1 से 5 वर्ष के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रूपए तक के नए अत्पावधि कृषि ऋण मूल राशि के समय पर भुगतान की शर्त पर प्रदान करेंगे।

☞ **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वैच्छिक पंजीकरण**- 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' ने सुनिश्चित किया है कि किसानों के लिए जोखिम कम हो और उन्हें बीमा की सुरक्षा मिले। हम इस योजना के तहत किसानों के स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान करेंगे।

☞ **नीतियों के जरिए किसानों का सशक्तिकरण**-हम कृषि आयात में कमी लाने और अनुमान-योग्य कृषि निर्यात एवं आयात नीति बनाने की दिशा में काम करेंगे, जिसमें कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा आयात को कम करने की एकीकृत व्यवस्था होगी।

☞ **गुणवत्तापूर्ण बीजों का वायदा**-हम यह सनिश्चित करेंगे कि संभावनायुक्त किस्मों के बेहतर बीज किफायती दरों पर किसानों को समय से उपलब्ध हों और घर के पास ही उनकी जांच की सुविधा उपलब्ध हो।

कृषि सहयोगी क्षेत्रों का विकास

☞ **तिलहन मिशन**-हम तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक नया मिशन आरम्भ करेंगे।

☞ **देश भर में वेयरहाउस नेटवर्क**-हम एक कुशल कृषि मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत भंडारण और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

• किसानों की आय बढ़ाने के उपाय के रूप में भंडारण पर हमारा ध्यान हमारी प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना से रेखांकित होता है। देश में भंडारण के आधारभूत ढांचे को और विस्तृत करने के लिए हम राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे राष्ट्रीय वेयरहाउसिंग ग्रिड स्थापित करेंगे, ताकि कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सुविधाएं सुनिश्चित हो सकें।

• किसानों को अपनी उपज का भंडारण अपने गांव के निकट करने तथा उचित समय पर उसे लाभकारी मूल्य पर बेचने के लिए समक्ष करने के उद्देश्य से हम कृषि उत्पादों के लिए नई 'ग्राम भंडारण योजना' आरम्भ करेंगे। हम कृषि उत्पादों की भंडारण रसीद के आधार पर किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे।

• जैविक खेती को बढ़ावा – जैविक खेती को अधिक-से-अधिक बढ़ावा देने और जैविक खेती को लाभप्रद बनाने के लिए, हम कदम उठाएंगे:

• हम अगले पांच वर्षों में पहाड़ी, आदिवासी एवं वर्षो-सिंचित क्षेत्रों में 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर रसायन मुक्त जैविक खेती को प्रोत्साहित करेंगे।

• हम उपभोक्ताओं के दरवाजे तक जैविक उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक समर्पित ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करेंगे।

• देश में गोशालाओं को जैविक खेती के प्रोत्साहन के साथ जोड़ा जाएगा।

• हम जैविक खेती वाले क्षेत्र के आसपास जैविक ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देंगे जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय भी सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन

किसानों के लिए अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने के लिए हम 'राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन' का आरम्भ करेंगे। हम बुनियादी ढांचागत सुविधाएं विकसित कर तथा विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराकर, शहद उत्पादन को 1,15,000 एम.टी. के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर दोगुना करेंगे।

सिंचाई का मिशन मोड पर विस्तार

हमने काफ़ी समय से लंबित 31 सिंचाई परियोजनाओं का कार्य 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के अंतर्गत प्राथमिकता से पूरा कर लिया है और शेष 68 परियोजनाओं का काम दिसंबर, 2019 तक चरणों में पूरा कर लिया जाएगा। सिंचाई के विकास के अपने प्रयास जारी रखते हुए हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का और भी विस्तार करेंगे ताकि समयबद्ध तरीके से देश की 100 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का उपयोग हो सके।

हम एक करोड़ हक्टेयर कृषि भूर्मि को सूक्ष्म-सिंचाई के अंतर्गत लाएंगे। इसके साथ ही उर्वरकों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'फर्टिगेशन' का सहारा लिया जाएगा।

कोऑपरेटिव

हम मानते हैं कि सहकारी संस्थाएं और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)कृषि क्षेत्र में बाजार तक बेहतर पहुंच एवं अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम उनकी सहायता करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम संसाधनों और बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने हेतु वर्ष 2022 तक 10,000 नए 'किसान उत्पादक संगठनों' के गठन में सहायता करेंगे।

बड़े शहरों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, हम किसानों के सहकारी संगठनों के जरिए सब्जियों, फलों, दूध एवं मत्स्य उत्पादों की सीधी मार्केटिंग प्रणाली स्थापित करेंगे ताकि किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके।

कृषि और प्रौद्योगिकी का मेल

हम किराए पर कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुगम करने के लिए मोबाईल पर आधारित प्रणाली तैयार करेंगे।

हम किसानों के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों के बाजार मूल्यों की बेहतर जानकारी सुनिश्चित करने हेतु तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देंगे।

हम युवा कृषि वैज्ञानिकों के विकास पर विशेष ध्यान देंगे तार्कि सटीक अनुमान वाली एवं अधिक लाभदायक खेती के लिए आर्टिफिशियल इटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स आदि का लाभ उठाया जा सके।

हम सौर ऊर्जा को किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्त्रोत की तरह देखते हैं और इसीलिए हम बड़े स्तर पर सौर फार्मिंग को बढ़ावा देंगे ताकि 'अन्नदाता' 'ऊर्जादाता' भी बन सके।

भूमि रिकॉर्डे का डिजिटलीकरण-आधार परियोजना की तर्ज पर हम मिशन मोड पर भूमि रिकॉर्ड का र्डिजिटलीकरण पूरा करेंगे। हम दूसरी पीढ़ी के भूमि सुधार लागू करेंगे ताकि भूमिधारकों को मालिकाना हक की गारटी मिले और जमीन से जुड़े मुकदमे कम हो सकें। हम (राज्यों के साथ सलाह कर) निश्चित स्वामित्व अधिकार का आदर्श कानून तैयार करेंगे जिसके माध्यम से भूस्वामित्व की सुनिश्चितता और बीमा को बढ़ावा मिले। इसे लागू करने के लिए हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।

पशुपालन- हमने डेयरी उद्योग को विशेष महत्व दिया है और गायों की देसी नस्लों के संरक्षण हेतु कामधेनु आयोग स्थापित किया है। हम किसानों को घर के नजदीक सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित करेंगे।

हम समय-समय पर सभी मवेशियों और अन्य पालतू जानवरों के स्वास्थ्य जांच के लिए जिला स्तर पर एक आदर्श कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे। इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से पशु चिकित्सकों की मदद ली जाएगी।

हम पशु टीकाकरण को और व्यापक बनाएंगे और खुरपका और मुंहपका तथा ब्रुसेलोसिस रोग का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे। हम चारे की कमी दूर करने के लिए 'राष्ट्रीय चारा एवं पशुआहार मिशन' आरम्भ करेंगे।

नीली क्रांति

हम छोटे एवं पारंपरिक मछुआरों की सुविधा के लिए आइस-बॉक्स, कोल्डस्टोरेज, आइस-प्लांट जैसे भंडारण एवं मार्केटिंग के साधनों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 10,000 करोड़ रूपए के आवंटन के साथ 'मठ संपदा योजना' आरम्भ करेंगे।

हम जल कृषि (एक्वा कल्चर) को बढ़ावा देने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराएंगे।

हम समुद्री वनस्पतियों और मोती की खेती एवं सजावटी मछलियों के पालन को बढ़ावा देंगे ताकि मछुआरों की आय में बढ़ोतरी हो सके। हम सभी मछुआरों को हर तरह केकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाएंगे और अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवर का लाभ भी प्रदान करेंगे।

किस राजनीतिक धरातल पर खड़ी है दीनदयाल की विरासत का दावा करने वाली भाजपा

गौतम चौधरी

भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसकी स्थापना भले 06 अप्रैल, सन् 1980 में हुई है लेकिन वह उसी जनसंघ का विस्तार है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव राव सदाशिव गोलवलकर की प्रेरणा से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर, सन् 1951 में गठित किया था। भाजपा का यह भी दावा है कि उसके सिद्धांत, कार्यपद्धति और सांगठनिक संरचना ठीक उसी प्रकार के हैं, जिस प्रकार जनसंघ के हुआ करते थे। हालांकि जब भाजपा के नेताओं से जनसंघ के जीवित होने की बात कही जाती है तो वे कन्नी काट जाते हैं। भाजपा दावा करती है कि वह पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों को अक्षरस: पालन करने वाली पार्टी है लेकिन क्या सचमुच भाजपा आज भी उसी राजनीतिक धरातल पर खड़ी है, जिसे दीनदयाल की जनसंघ ने तैयार किया था?

आज इस विषय पर पड़ताल जरूरी है। दीनदयाल के भाषण और दैनिक डायरी पर आधारित कुछ किताबों के अध्ययन से साफ जाहिर होता है कि वे इस देश की सांस्कृतिक आत्मा के चिंतक थे। दीनदयाल, महात्मा गांधी और डॉ. राममनोहर लोहिया के चिंतन का विस्तार है लेकिन आज की भाजपा में दीनदयाल कहां खड़े हैं इसपर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। दीनदयाल चिंतन के दो आधार हैं। पहला एकात्मवाद और दूसरा अन्योदय। हालांकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतकों की ही उपज है लेकिन दीनदयाल के चिंतन में इसकी चर्चा नहीं के बराबर है। इन तमाम उहापोहों के बीच कई स्तरों पर विमर्श जारी है। यह विमर्श न केवल बाहरी लोगों के बीच हो रहा है अपितु संघ और भाजपा के अंदर भी इस बात को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है।

भाजपा आखिर किसकी विरासत का प्रतिनिधित्व करती है इस विषय पर कई विद्वानों के अलग – अलग मत हैं। प्रोफेसर देवेन्द्र स्वरूप ने बताया कि जब सन् 1947 में देश का विभाजन हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। संघ के कुछ कार्यकर्त्ता यह चाहते थे कि संघ भी एक राजनीतिक दल की तरह काम करे लेकिन संघ के तत्कालीन सरसंघचालक, माधवराव सदाशिव गोलवलकर इसके विरुद्ध थे। उन दिनों संघ की दृष्टि से पूरा उत्तर भारत एक प्रांत हुआ करता था और उसके प्रांत प्रचारक बसंत राव ओक हुआ करते थे। बसंत राव गोलवलकर के विचार से सहमत नहीं थे। हालांकि इसी असहमति के कारण उन्हें संगठन छोड़ना भी पड़ा था लेकिन उनके संरक्षण में कई स्थानों पर संघ के स्वयंसेवकों ने जनसंघ नामक राजनीतिक दल का गठन कर लिया। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कई शहरों में व्यापक स्तर पर हुआ। रांची के रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेव संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्त्ता हरीश कपूर ने मुझे व्यक्तिगत बातचीत में बताया था कि उन दिनों लखनऊ और कानपुर में भी स्थानीय स्तर पर जनसंघ नामक राजनीतिक दल का गठन कर लिया गया। उस दल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्त्ता शामिल हो गए। हरीश कपूर ने तो यहां तक बताया कि जनसंघ की पहली बैठक उनकी लखनऊ वाली चश्मे की दुकान, बीएन वैजल पर ही हुई थी।

वह दौर सन् 48 – 50 का था। इसी दौरान गांधी जी हत्या हुई और आरएसएस के नेताओं का आरोप है कि संघ की लोकप्रियता को खत्म करने के लिए देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। हरीश कपूर के अनुसार माधवराव भी संसद में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दल के पक्ष में थे लेकिन वे राजनीतिक दलों की विसंगतियों से वाकिफ थे इसलिए वे राजनीतिक दल वाले प्रयोग से परहेज कर रह रहे थे। आरएसएस पर प्रतिबंध के बाद माधवराव को हिन्दुओं के हितों की चिंता करने वाली पार्टी की जरूरत महसूस हुई। लगा कि संसद में हिन्दुओं का पक्ष रखने वाले दल के अभाव के कारण हिन्दू समाज का अहित हो रहा है। इस चिंतन के बाद उन्होंने भी राजनीतिक दल के प्रयोग की योजना बना ली। इसी बीच उनकी मुलाकात संवित सरकार के काबीना मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई और जनसंघ को अखिल भारतीय स्वरूप देने की योजना बन गयी।

देवेन्द्र स्वरूप कहते हैं कि देश के कई शहरों में जनसंघ का गठन तो पहले हो चुका था, 21 अक्टूबर 1951 को तो महज घोषणा की गयी। इसी प्रकार की कुछ बातें पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ पुराने संघ कार्यकर्त्ताओं ने भी बताई। जो भी हो, सन् 51 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक, माधवराव सदाशिव गोलवलकर अपने कुछ प्रमुख और योग्य कार्यकर्त्ताओं को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लाए और जनसंघ का स्वरूप अखिल भारतीय बन गया।

आधिकारिक रूप से जनसंघ का गठन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गयी थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह लैंप था। इसने 1952 के संसदीय चुनाव मे दो सीटें हासिल की थी, जिसमे डॉक्टर मुखर्जी स्वयं भी शामिल थे। हालांकि एक पार्टी के रूप में जनसंघ आज भी जिंदा है लेकिन प्रभावशाली तरीके से सन् 1977 तक जनसंघ भारतीयता का नेतृत्व करता रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद, मौलिचन्द्र शर्मा (1954), प्रेम नाथ डोगरा (1955), आचार्य देव प्रसाद घोष (1956 – 59), पीताम्बर दास (1960), अवसरला राम राव (1961), आचार्य देव प्रसाद घोष (1962), रघुवीर (1963), आचार्य देवप्रसाद घोष (1964), बछराज व्यास (1965), बलराज मधोक (1966), दीनदयाल उपाध्याय (1967 – 68), अटल बिहारी वाजपेयी (1969 – 72), लालकृष्ण आडवाणी (1973 – 77) अध्यक्ष बनाए गए।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल (1975 – 1976) के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनैतिक दलों का विलय करके एक नए दल, जनता पार्टी का गठन किया गया। आपातकाल से पहले बिहार विधानसभा के भारतीय जनसंघ के विधायक दल के नेता लालमुनि चौबे ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बिहार विधानसभा से अपना त्यागपत्र दे दिया। दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी 1980 में टूट गयी और जनसंघ की विचारधारा के नेताओं ने 06 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी नाम का एक नया राजनीतिक दल अस्तित्व में आया।

यह दौर जम्मू – कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद का दौर था। सन् 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गयी। इस सहानुभूति लहर में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी खुद ग्वालियर से चुनाव हार गए। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि उस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कांग्रेस का साथ दिया था। उस चुनाव में मात्र दो सीटों पर भाजपा जीत पायी। इसके बाद सन् 1986 में लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने फिर से हिन्दुत्व के मुद्दे को अपने पार्टी एजेंडे में शामिल किया और विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा चलाए जा रहे राम जन्मभूमि मंदिर आन्दोलन को संरक्षण देना प्रारंभ किया। इस योजना को भारत की जनता ने हाथोंहाथ लिया और भारतीय जनता पार्टी दो सीटों से 85 पर पहुंच गयी। लालकृष्ण आडवाणी सन् 1990 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। पार्टी के बहुमत में आने के बाद भले लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए लेकिन पार्टी को जीवित करने में उनकी भूमिका इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

सन् 1991 में डॉ. मुरली मनोहर जोशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में पार्टी के 120 सांसद लोकसभा पहुंचे। इसके बाद सन् 1995 में पार्टी ने कई राज्यों के विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें बिहार, ओड़ीस, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा आदि शामिल है। इन्हीं दिनों कुछ राज्यों में पार्टी ने सरकार का भी गठन किया। 1996 में पार्टी ने लोकसभा की 161 सीटें जीती जबकि 1998 से 2004 तक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा रही और गठबंधन का नेतृत्व किया। 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन हुआ और भाजपा के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक गठबंधन का पराजय हुआ। संप्रग की सरकार बन गयी। पार्टी को 186 संसद का समर्थन मिला जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। 2004 से लेकर 2014 तक भाजपा मुख्य विपक्ष की भूमिका में रही। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी कमजोर पड़ गयी और मात्र 116 लोकसभा के सीटों जीत पायी। इस बीच भाजपा राज्यों में अपनी ताकत बढ़ाती रही और 2014 के आम चुनाव में इसने अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। यह करिश्मा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के कारण ही संभव हो पाया। सन् 2013 में नरेन्द्र मोदी को पार्टी ने प्रधानमंत्री का कंडीडेट घोषित कर दिया। पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह को सौंपा गया। इस पूरे चुनाव के रणनीतिकार वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह को बनाया गया। इस प्रकार पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव अपार बहुमत से जीत गयी। यह जीत पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी। हालांकि इसके बाद दिल्ली, पंजाब आदि राज्यों में पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तरराखंड में पार्टी ने फिर से सत्ता हासिल कर यह साबित कर दिया कि पार्टी का अगर एजेंडा सही रास्ते पर है तो पार्टी किसी कीमत पर कमजोर नहीं हो सकती है।

यदि हम यह मान लें कि भाजपा सचमुच जनसंघ की विरासत की पार्टी है तो जिस स्थान से इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की और यात्रा के समय, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया, वह पूरा होता नहीं दिख रहा है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विरासत आज नरेन्द्र दामोदर दास मोदी व अमित भाई शाह के पास है। जनसंघ के उन दो नेताओं के व्यक्तित्व के सामने ये दोनों कहां खड़े हैं इसकी जानकारी आज सबको है। नि:संदेह भाजपा आज सबसे प्रभावशाली पार्टी बन गयी है। आज इस पार्टी के पास जितनी संपत्ति, संसाधन, कार्यकर्त्ता और ताकत है उतना देश के किसी भी पार्टी के पास नहीं है। यह पार्टी अन्य पार्टियों की अपेक्षा ज्यादा संगठित और अनुशासित भी है लेकिन चाल, चरित्र और चेहरे के मामले में क्या यह अन्य पार्टियों से अलग है? यह भाजपा के नेताओं को सोचना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस विषय पर सोचना चाहिए कि वह जिस पार्टी को आजतक संरक्षण देती रही है वह समाज, देश एवं खुद संगठन के लिए कितना उपयोगी है? खुद संघ और भाजपा के कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि सिद्धांत, कार्यपद्धति और नेताओं के व्यक्तित्व के मामले में भाजपा अब अन्य पार्टियों की तुलना में ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। हिन्दुत्व, अन्त्योदय, सर्वांगिण विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी भाजपा का रवैया ढुलमुल रहा है। यही कारण है कि पांच साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी भाजपा अपने एक भी पारंपरिक मुद्दों को देश में स्थापित नहीं कर पायी। गौर से देखें तो नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार अपने सैद्धांतिक मुद्दों पर तीन साल तक कोई पहल करती नहीं दिखी। तीन साल के बाद मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता का आधा – अधूरा काम करने की सोची और तीन तलाक बिल पर अध्यादेश लेकर आ गयी। यही हाल धारा 370 और अनुच्छेद 35ए का भी है। खुद भाजपा के कार्यकर्त्ताओं का आरोप है कि राम जन्मभूमि मंदिर के मामले में भी नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ठीक से पहल नहीं की। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भाषण तो खूब दिए गए लेकिन सैन्य टुकड़ियों के सशक्तिकरण पर पूरे पांच साल कोई ध्यान नहीं दिया गया। मोदी की सरकार ने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाया और विदेशी संबंधों के मामले में भी महाशक्तियों से समान दूरी बनाने के अपने पारंपरिक सिद्धांत से अलग दिखी। यहां तक कि मोदी सरकार ने चीन के साथ गैरपारंपरिक तरीके से संबंध स्थापित करने की कोशिश की। ये तमाम चिंतन और कार्य जनसंघ के सिद्धांतों के इतर हैं। स्वदेशी, स्वावलंबन और सुरक्षा के मामले में भी मोदी सरकार समझौता करती दिखी। यदि सचमुच मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सजग होती तो जम्मू – कश्मीर के हालात खराब नहीं होते। डोकलाम पर चीनी दबाव के सामने भारत की स्थिति बेहतर होती। माओवादी आतंकवाद पर लगाम लगता और पाकिस्तान की ओर से बढ़ रहे चुनौतियों का सामना करने में भारत सक्षम होता लेकिन आज के हालात पहले से अच्छे नहीं हुए हैं।

आर्थिक मोर्चे पर भी देश की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। दूसरी ओर नरेन्द्र मोदी के शासन काल में एक बार फिर से नौकरशाही की ताकत बढ़ गयी है। कॉरपोरेट लूट में कमी नहीं आयी है। भ्रष्टाचार के मामले चल तो रहे हैं लेकिन पांच सालों में एक भी भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा के नेताओं के आय में दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि हो रही है। यह साबित करता है कि भाजपा के नेता भी भ्रष्ट हैं और अब भ्रष्टाचार भाजपा के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ऐसे में अगर भाजपा यह कहती है कि वह दीनदयाल के विरासत की पार्टी जनसंघ का प्रतिनिधित्व करती है तो यह सरासर गलत है। हां कुछ मामले में मोदी सरकार ने सकारात्मक पहल की है, जैसे सीटीजनशिप चार्टर का मामला। इस मामले में पहल तो की है लेकिन वह पहल भी राजनीतिक ही लग रही है। वैसे ही जम्मू – कश्मीर में मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्य भी बहुसंख्यक ध्रुवीकरण का ही मामला लगता है, जबकि दीनदयाल और जनसंघ के चिंतन में यह कहीं नहीं दिखता है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि भाजपा चाहे कुछ भी दावा कर ले लेकिन दीनदयाल के चिंतन से कोसों दूर हो चुकी है नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की भाजपा।

हिमाचलवासियों को

72वें हिमाचल दिवस

के पावन अवसर पर

प्रदेश सरकार

की ओर से

हार्दिक बधाई

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सुखराम परिवार के गिर्द केन्द्रित होता जा रहा यह चुनाव

शिमला/शैल। जयराम सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा को मण्डी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा प्रत्याक्षी बनाये जाने के बाद प्रदेश का लोकसभा चुनाव सुखराम परिवार बनाम भाजपा होता जा रहा है। क्योंकि बेटे को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद सबसे पहले यह मुद्दा बना कि अनिल शर्मा मण्डी में भाजपा प्रत्याशी के लिये चुनाव प्रचार करें। जब अनिल ने ऐसा करने में असमर्थता जताई तो फिर यह मुद्दा अनिल के मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देने का बन गया। अब जब अनिल ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया है तो मुद्दा विधानसभा की सदस्यता से भी नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने का बन गया है। पूरी भाजपा का हर बड़ा छोटा नेता अनिल का त्यागपत्र मांगने लग गया है। इस तरह पूरी प्रदेश भाजपा का केन्द्रिय मुद्दा अनिल शर्मा बना गया है और यह मुद्दा बनना ही सुखराम परिवार की पहली रणनीतिक जीत है।

जब सुखराम अपने पौत्र को कांग्रेस का टिकट दिलाने में सफल हो गये हैं तो यह तय है कि देर सवेर अनिल शर्मा भाजपा से किनारा कर ही लेंगे। लेकिन ऐसा कब होगा यह इस समय का सबसे अहम सवाल है। अनिल भाजपा के टिकट पर जीत कर आये हैं और तभी मन्त्री बने थे इस नाते वह पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं। पार्टी अनुशासन के खिलाफ जाने पर पार्टी सदस्य के खिलाफ कारवाई करके सदस्य को पार्टी से बाहर निकाल सकती है। जो व्यक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक या सांसद बना हो उसकी सदन से सदस्यता तब तक समाप्त नही की सकती है जब तक वह सदन में पार्टी द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन न करे। सदन के बाहर कोई भी सांसद/विधायक पार्टी की नीतियों/फैसलों पर अपनी अलग राय रख सकता है। अलग राय रखने के कारण सदन की सदस्यता रद्द नही की जा सकती है। यह नियमों में स्पष्ट कहा गया है। पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद इसके अभी प्रत्यक्ष और ताजा उदाहरण हैं। इसलिये अभी मानसून सत्र तक अनिल की सदस्यता को कोई खतरा नही है। ऐसे में अनिल के लिये यह राजनीतिक आवश्यकता हो जाती है कि वह सार्वजनिक चर्चा में आने के लिये पूरे दृश्य को ऐसा मोड़ देते कि पूरा राजनीतिक परिदृश्य उन्ही के गिर्द घूम जाता और वह ऐसा करने में पूरी तरह सफल भी रहे हैं।

जब भाजपा और मुख्यमन्त्री जयराम ने उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर यह कहा कि उनका मन्त्री गायब हो गया है और घर में घास काट रहा है तब अनिल को पलटवार करने का मौका मिला और उसने सीधे कहा कि जब चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है तो फिर मन्त्री घास क्यों नही काट सकता। इसके बाद यह वाकयुद्ध आगे बढ़ा और अनिल ने जयराम को बाईचांस बना मुख्यमन्त्री करार दे दिया। इस पर जब जयराम ने जबाव दिया तब अनिल ने मण्डी में स्वास्थ्य और सड़क सेवाओं के मुद्दे पर घेर लिया। आज पूरे प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सेवाओं की बुरी हालत है। शिक्षा में प्राईवेट स्कूलों की लूट को लेकर छात्र – अभिभावक मंच आन्दोलन की राह पर हैं। सरकार अदालत के फैसले पर अमल नही करवा पायी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन स्कूलों की लूट को अपरोक्ष में सरकार का समर्थन हासिल है। इसलिये आज तक इस आन्दोलन को लेकर मुख्यमन्त्री और शिक्षा मंत्री की ओर से कोई सीधी प्रतिक्रिया नही आयी है। इसलिये अब अनिल शर्मा जब जयराम के मन्त्री नही रहे हैं तब सरकार के हर फैसले पर अपनी राय सार्वजनिक रूप से रख सकते हैं। वह सरकार के फैसलों की आलोचना कर सकते हैं। अनिल शर्मा

सरकार में मन्त्री रहे हैं इसलिये सरकार की हर नीति की जानकारी उनको होना स्वभाविक है। सरकार की प्राथमिकताएं क्या रही हैं और उन पर किस मन्त्री का क्या स्टैण्ड था यह सब अनिल के संज्ञान में निश्चित रूप से रहा होगा। क्योंकि जिस सरकार को वित्त वर्ष के पहले ही सप्ताह में अपनी धरोहरों की निलामी करके कर्ज उठाना पड़ जाये उस सरकार की हालत का अन्दाजा लगाया जा सकता है। आज सरकार की हालत यह है कि सारे निगमों/बोर्डो में राजनेताओं को तैनातीयां नही दे पायी है। सरकार में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के पद अभी तक नही भरे जा सके हैं। राईट टू फूड के तहत नियमित फूड कमीश्नर की नियुक्ति नही हो पायी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरैन्स का दावा करने वाली सरकार आज तक लोकायुक्त की नियुक्ति नही कर पायी है। यहां तक कि नगर निगम शिमला में मनोनीत पार्षदों का मनोनयन नही हो पाया है। यह सवाल उठ रहा है कि सरकार ने लोकसेवा आयोग में तो पद सृजित करके अपने विश्वस्त की ताजपोशी कर दी लेकिन अन्य अदारे आपकी प्राथमिकता नही रहे। ऐसा क्यों हुआ है हो सकता है कि इस बारे में बहुत सारी जानकारियां अब सामने आयें और उनका माध्यम अनिल शर्मा बन जायें।

अनिल शर्मा से नैतिकता के आधार पर सदन से त्यागपत्र मांगा जा रहा है। सुखराम पर पार्टी से विश्वासघात का आरोप लगाया जा रहा है। शान्ता कुमार ने कहा कि वह सुखराम को भाजपा में शामिल करने के पक्ष में नही थे। शान्ता ने यह भी कहा कि सुखराम से पूरे देश में भाजपा की बदनामी हुई है। सुखराम ने यह कहा कि उनके कारण भाजपा को 43 सीटें हालिस हुई हैं। इस तरह सुखराम/अनिल को केन्द्रित करके इतने मुद्दे खड़े हो गये हैं कि चुनाव में उन मुद्दों से ध्यान हटाना संभव नही होगा। भाजपा जब नैतिकता की बात करती है तो पहला सवाल यह उठता है कि इसी भाजपा ने 1996 में सदन के अन्दर एक लघुनाटिका प्रदर्शित की थी उसमें किश्न कपूर और जब जेपी नड्डा ने अनिल-सुखराम के किरदार निभाये थे। लेकिन उसके बाद 1998 में सुखराम के सहयोग से सरकार बनायी और पांच वर्ष चलायी भी। तब क्या भाजपा की नैतिकता कोई दूसरी थी? क्या भाजपा नेता आज नैतिकता दिखायेंगे कि सार्वजनिक रूप से कहे कि 1998 में सुखराम के सहयोग से सरकार बनाना और चलाना दोनो अनैतिक थे। इसके बाद अब 2017 में जब अनिल को भाजपा में शामिल किया और फिर मन्त्री बनाया तब क्या भाजपा के आरोपपत्र में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नही था? क्या सत्ता के लिये उस आरोप को नज़रअन्दाज नही किया गया? क्या यह प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात नही था। क्या इस परिदृश्य में भाजपा से यह सवाल नही बनता है कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कब क्या कारवाई की? शान्ता कुमार ने 1992 में होटल यामिनी के बदले में अपनी प्राईवेट ज़मीन का तबादला करवाया। सचिवालय से यह लिखा गया कि विशेष परिस्थितियों में इसकी अनुमति दी जाती है। ऐसी सुविधा प्रदेश में कितने लोगों को दी गयी है। 1998 में धूमल सरकार में चिट्टों पर हज़ारों लोगों की भर्तीयों का मामला सामने आया। सरकार ने हर्ष गुप्ता और अभय शुक्ला के अधीन दो जांच कमेटीयां बैठाई। इन कमेटीयों की रिपोर्ट में सनसनी खेज खुलासे सामने आये। लेकिन अन्त में सरकार ने कोई कारवाई नही की। अब जयराम सरकार के सामने फिर भाजपा द्वारा सौंपा हुआ आरोप पत्र सामने है। इसी आरोप पत्र में अनिल के खिलाफ आरोप था। भाजपा इस आरोप पत्र पर कारवाई नही कर पायी है। इसके अतिरिक्त दर्जनों और मामले हैं जहां भाजपा की नैतिकता पर गंभीर सवाल उठते हैं। आज भी भ्रष्टाचार जारी है। ऐसे में भाजपा जब सुखराम और अनिल की नैतिकता पर सवाल उठायेगी तब सबसे पहले उसी की नैतिकता उसके सामने आ जायेगी। विश्लेष्कों के मुताबिक मुख्यमन्त्री के सलाहकारों ने ही मुख्यमन्त्री को आज संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। इन्ही सलाहकारों के कारण यह चुनाव सुखराम परिवार के गिर्द केन्द्रित होता जा रहा है।

प्रदेश की सेहत बिगाड़ने के कगार पर पहुंचा मोदी का आयुष्मान

शिमला/शैल। मोदी सरकार ने देश के दस करोड़ गरीबों की सेहत की चिन्ता करते हुए एक महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब आदमी पांच लाख के खर्चे तक का मुफ्त ईलाज करवा सकता है। इसके लिये इन गरीब लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। ईलाज करवाने आये व्यक्ति को संबंधित अस्पताल में यह कार्ड दर्ज करवाकर अपना मुफ्त ईलाज करवाने की सुविधा है। इस ईलाज में दवाईयों पर ही इतना खर्च आये या आप्रेशन में यह खर्च आये अस्पताल यह पैसा मरीज से वसूल नही करेगा। आयुष्मान भारत योजना को और सहारा देने के लिये प्रदेश सरकार ने भी अपनी ओर से हिमकेयर योजना शुरू कर रखी है। यह योजनाएं देखने और सुनने में जितनी आकर्षक हैं इनका व्यवहारिक पक्ष उतना ही कठिन है। यदि मरीज के साथ कम से कम दो आदमी साथ आये हों और अस्पताल का स्टॉफ ईमानदारी से उनका सहयोग करें तभी यह ईलाज संभव है अन्यथा नही।

आईजीएमसी प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है। यहां पर पिछले वर्ष करीब आठ लाख मरीज ईलाज के लिये आये हैं जिनमें हजारों ऐसे रहे हैं जो इन कार्डो के सहारे आये थे। लेकिन इन कार्डो पर दवाई लेने के लिये इतनी लम्बी और पेचीदा प्रक्रिया बना रखी है कि आदमी अन्त में तंग आकर कार्ड पर ईलाज करवाना ही छोड़ देता है। मरीज को दाखिल करवाने और फिर ठीक होने पर डिस्चार्ज लेने के लिये इतनी लम्बी और पेचीदा प्रक्रिया बना रखी है कि कई मरीज ईलाज के डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया को पूरा किये बिना ही अस्पताल छोड़कर चले जाते

हैं। आईजीएमसी में पिछले एक साल में 900 से अधिक मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिनके ईलाज पर संस्था की ओर से तो करीब चार करोड़ खर्च कर दिये गये हैं लेकिन अस्पताल को यह पैसा वापिस नही मिला है क्योंकि इसमें दाखिल होते समय और फिर छुट्टी करते हुए सारी प्रक्रियाओं को पूरा नही किया गया है। यह प्रक्रियाएं पूरी न होने के कारण भारत सरकार यह पैसा हिमाचल सरकार या आईजीएमसी को रिफण्ड नही कर रही है। यहां पर यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब मरीज को दाखिल करते वक्त यह कार्ड रिकार्ड पर दर्ज कर लिया जाता है तो फिर उसे अस्पताल से छुट्टी होने तक बार-बार कार्ड दर्ज करवाने की जरूरत क्यों हो।

इन कार्डो के तहत ईलाज करवाने के लिये हर बिमारी के लिये ईलाज का एक पैकेज तैयार किया जाता है। किसी भी बीमारी में यह पैकेज पांच लाख का नही है। लेकिन फिर भी बीमारी में मरीज को अपनी जेब से कुछ न कुछ खर्च करना पड़ ही जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है इसका डाक्टरों के पास कोई संतोषजनक जवाब नही है। कार्डधारक के सारे टैस्ट फ्री होने होते हैं। आईजीएमसी मे टैस्टों के लिये प्राईवेट लैब एसएलआर काम कर रही है इसको अस्पताल की ओर से जगह भी दे गयी है। लेकिन यह लैब सारे टैस्ट फ्री में नही कर रही है। पिछले दिनों जब इस आश्य की शिकायतें अस्पताल के प्रबन्धन के पास पहुंची तब प्रबन्धन ने लिखित में लैब से जवाब मांगा। लेकिन जवाब मांगने पर लैब के स्थानीय प्रबन्धन ने जवाब दिया कि यह फ्री टैस्ट उनके एमओयू में शामिल ही नही है और इसका जवाब दिल्ली से आयेगा। लैब के साथ हुई इस कारवाई के बाद यह सामने आया है कि लैब के साथ एमओयू दिल्ली में नड्डा के मन्त्रालय के साथ हुआ है और उसमें क्या टैस्ट फ्री होने हैं इसकी सूची तक आईजीएमसी प्रबन्धन या राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध नही है। इसी तरह सरकार की हिमकेयर योजना के तहत भी सप्लायरों को पैसा नही दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिमला के मनचन्दा जैसे सप्लायर का ही करोड़ो का बिल कई दिनों से भुगतान के लिये फंस गया है। सप्लायरों की हालत यह हो गयी है कि वह आगे सप्लाई देने की स्थिति में नही है। ऐसे में जब आयुष्मान और हिमकेयर जैसी योजनाओं में आईजीएमसी का ही करीब पांच करोड़ फंस गया है तो प्रदेश के अन्य अस्पतालों में स्थिति कहां तक पहुंच गयी होगी और इस परिदृश्य में यह योजनाएं आगे कितना समय चल पायेगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।